



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की

खण्ड-17] रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 ई0 (पौष 03, 1938 शक सम्वत्) [संख्या-52

विषय-सूची

प्रत्येक भाग के पृष्ठ अलग-अलग दिये गए हैं, जिससे उनके अलग-अलग खण्ड बन सकें

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्द
		रु0
सम्पूर्ण गजट का मूल्य ...	—	3075
भाग 1-विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस ...	631-639	1500
भाग 1-क-नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया ...	755-763	1500
भाग 2-आज्ञाएं, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों के उद्धरण ...	—	975
भाग 3-स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, नगर प्रशासन, नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया एवं निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा पंचायतीराज आदि के निदेश जिन्हें विभिन्न आयुक्तों अथवा जिलाधिकारियों ने जारी किया ...	—	975
भाग 4-निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 5-एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तराखण्ड ...	—	975
भाग 6-बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने से पहले प्रकाशित किए गए तथा सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट ...	—	975
भाग 7-इलेक्शन कमीशन ऑफ इण्डिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां ...	—	975
भाग 8-सूचना एवं अन्य वैयक्तिक विज्ञापन आदि ...	—	975
स्टोर्स पर्चेज-स्टोर्स पर्चेज विभाग का क्रोड़-पत्र आदि ...	—	1425

भाग 1

विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान—नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

08 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 2499/X-1-2016-04(23)/2009—श्री संजीव चतुर्वेदी, भा०व०से० (2002) को नियमित चयनोपरान्त वन संरक्षक, वेतनमान ₹ 37,400-67,000 ग्रेड पे ₹ 8900, में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

08 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 2500/X-1-2016-04(23)/2009—श्री अशोक, भा०व०से० (1996) को नियमित चयनोपरान्त मुख्य वन संरक्षक, वेतनमान ₹ 37,400-67,000 ग्रेड पे ₹ 10,000 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने एवं अग्रिम आदेशों तक प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय में सम्बद्ध करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

08 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 2501/X-1-2016-04(23)/2009—श्री जन्मेजय सिंह, भा०व०से० (1998) को नियमित चयनोपरान्त मुख्य वन संरक्षक, वेतनमान ₹ 37,400-67,000 ग्रेड पे ₹ 10,000 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

एस० रामास्वामी,
अपर मुख्य सचिव।

गृह अनुभाग-1

कार्यालय ज्ञाप

23 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 1487/XX-1/16-03(19)2007—अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि “उत्तराखण्ड पुलिस सेवा नियमावली-2009” के नियम-25 के अन्तर्गत श्री मिथिलेश कुमार सिंह व श्रीमती जया बालोनी, सीधी भर्ती के पुलिस उपाधीक्षकों को दिनांक 14-01-2013 से प्रान्तीय पुलिस सेवा उत्तराखण्ड में स्थाई किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,

डॉ० उमाकान्त पंवार,
प्रमुख सचिव।

पर्यटन अनुभाग

कार्यालय ज्ञाप

28 अक्टूबर, 2016 ई०

संख्या 2423/VI(1)/2016-04(03)/2011-वरिष्ठ शोध अधिकारी पर्यटन के पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 25 अक्टूबर, 2016 को आयोजित विभागीय चयन समिति की संस्तुति के आधार पर श्री सुरेन्द्र सिंह सामन्त, शोध अधिकारी पर्यटन को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ शोध अधिकारी पर्यटन के पद पर वेतनमान ₹ 15600-39100, ग्रेड वेतन ₹ 6600/- में पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

परिवहन अनुभाग-1

अधिसूचना

04 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 1129/2016/84/IX-1/2016-श्री राज्यपाल महोदय, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या-10, सन् 1897) की धारा 21 और उत्तर प्रदेश मोटरयान (अनुपूरक) नियमावली, 1989 के नियम 8 के खण्ड (ग) के साथ पठित मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, सन् 1989) की धारा 68 की उपधारा (1) और (2) सपठित उत्तराखण्ड मोटरयान नियमावली, 2011 के नियम 56 के उप नियम (8) (दो) के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए और इस सम्बन्ध में पूर्व में जारी अधिसूचना संख्या 716/30-4-135/80, दिनांक 27 मार्च, 1998 एवं अधिसूचना संख्या 507/3-7/स0परि0/कैम्प/2001, दिनांक 18 अप्रैल, 2001 विखण्डित करते हुए, राज्य के राज्य परिवहन प्राधिकरण एवं संभागीय परिवहन प्राधिकरणों के गठन एवं संचालन तथा कृत्यों के निर्वहन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों के रूप में निम्नानुसार गठन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

क्र० सं०	परिवहन प्राधिकरण का नाम	परिवहन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्य	संभाग का नाम	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5
1.	राज्य परिवहन प्राधिकरण, देहरादून	(1) आयुक्त परिवहन, अध्यक्ष (2) अपर सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, उत्तराखण्ड शासन, सचिव (3) मुख्य अभियन्ता स्तर 1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, सदस्य (4) शासन द्वारा नामित दो गैर सरकारी सदस्य उप परिवहन आयुक्त से अन्यून अधिकारी, पदेन सचिव	—	राज्य स्तर

1	2	3	4	5
2.	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, देहरादून	(1) आयुक्त गढ़वाल मण्डल, अध्यक्ष (2) शासन द्वारा नामित दो गैर सरकारी सदस्य संभागीय परिवहन अधिकारी, देहरादून, पदेन सचिव	देहरादून संभाग	उत्तरकाशी, टिहरी, हरिद्वार, देहरादून जिले
3.	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, पौड़ी	(1) आयुक्त गढ़वाल मण्डल, अध्यक्ष (2) शासन द्वारा नामित दो गैर सरकारी सदस्य संभागीय परिवहन अधिकारी, पौड़ी, पदेन सचिव	पौड़ी संभाग	पौड़ी, चमोली, रूद्रप्रयाग जिले
4.	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, हल्द्वानी (नैनीताल)	(1) आयुक्त कुमायूँ मण्डल, अध्यक्ष (2) शासन द्वारा नामित दो गैर सरकारी सदस्य संभागीय परिवहन अधिकारी, हल्द्वानी (नैनीताल), पदेन सचिव	कुमायूँ संभाग	नैनीताल, चम्पावत ऊधमसिंह नगर जिले
5.	संभागीय परिवहन प्राधिकरण, अल्मोड़ा	(1) आयुक्त कुमायूँ मण्डल, अध्यक्ष (2) शासन द्वारा नामित दो गैर सरकारी सदस्य संभागीय परिवहन अधिकारी, अल्मोड़ा, पदेन सचिव।	कुमायूँ संभाग	अल्मोड़ा, बागेश्वर पिथौरागढ़ जिले

आज्ञा से,
सी0 एस0 नपलच्याल,
सचिव।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

23 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 1878/XXXII/2016/37(02)/2016-तात्कालिक प्रभाव से श्री रविन्द्रा पाण्डे, मुख्य व्यवस्थाधिकारी, को नियमित चयनोपरान्त मुख्य व्यवस्थाधिकारी (सी०ग्रे०) वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 7600, के रिक्त पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए, वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री रविन्द्रा पाण्डे को संगत नियमावली के नियम-10 अधीन दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3-श्री पाण्डे को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपनी तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

23 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 1879/XXXII/2016/37(02)/2016-तात्कालिक प्रभाव से श्री नवीन चन्द्र उप्रेती, वरिष्ठ व्यवस्थाधिकारी, को नियमित चयनोपरान्त मुख्य व्यवस्थाधिकारी वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 6600, के रिक्त पद पर अस्थाई रूप से पदोन्नत करते हुए, वर्तमान तैनाती के स्थान पर तैनात किये जाने की महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2-उक्त पदोन्नति के फलस्वरूप श्री नवीन चन्द्र उप्रेती, को संगत नियमावली के नियम-10 अधीन दो वर्ष तक परिवीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3-श्री उप्रेती को निर्देशित किया जाता है, कि वे अपनी तैनाती के स्थान पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक की प्रति राज्य सम्पत्ति अनुभाग-3, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

सी० एस० नपलच्याल,
सचिव।

कार्मिक अनुभाग-1

विज्ञप्ति/सेवानिवृत्ति

23 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 2515(B)/XXX-1/2016-25(2)04-अद्योहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) के निम्नांकित तालिका में उल्लिखित अधिकारी राज्य सिविल सेवा (कार्यकारी शाखा) में अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के उपरान्त उनके नाम के सम्मुख कॉलम 04 में अंकित तिथि के अपरान्तः में राजकीय सेवा से सेवानिवृत्त हो जायेंगे :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4
1.	श्री हिमालय सिंह	26-01-1957	31-01-2017

आनन्द वर्द्धन,
सचिव।

सहकारिता एवं गन्ना चीनी अनुभाग-1

आदेश/पदोन्नति

29 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 1252/XIV-1/2016-9(5)2010-सहकारिता विभाग के अन्तर्गत सहकारी निरीक्षक वर्ग-1 से सहायक निबन्धक के पद पर पदोन्नति के सम्बन्ध में दिनांक 16 सितम्बर, 2016 को सम्पन्न चयन समिति की बैठक में रिक्त पदों पर योग्यता के आधार पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग, उत्तराखण्ड द्वारा संस्तुत निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित कार्मिकों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ के पद पर (पे बैंड-3 वेतनमान ₹ 15600-39100 ग्रेड वेतन ₹ 5400) नियमित रूप से पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. श्री अनिल कुमार,
2. श्री नरेन्द्र सिंह रावत,
3. श्री दुर्गा सिंह,
4. श्री हरीश चन्द्र खण्डुडी,
5. श्री मनोज कुमार पुनेठा,
6. श्री सुरेन्द्र पाल,
7. श्री मनोहर सिंह मर्तोलिया।

2-उक्त पदोन्नत अधिकारियों को सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाता है।

3-उपरोक्त अधिकारियों द्वारा कार्यभार प्रमाणक निबन्धक, सहकारी समितियाँ, उत्तराखण्ड तथा शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा। पदोन्नत अधिकारियों की तैनाती के आदेश पृथक से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,

विजय कुमार ढौंडियाल,
सचिव।

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना

30 नवम्बर, 2016 ई०

संख्या 2561/VI(1)/2016-01(04)/2013-अधिसूचना संख्या 114, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 की धारा-4(1) एवं (2) में दी गयी व्यवस्थानुसार अधिसूचना संख्या 1522, दिनांक 27 नवम्बर, 2013 द्वारा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा अधिनियम की धारा-4(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार अधिसूचना संख्या 288, दिनांक 09 मार्च, 2016 तथा अधिसूचना संख्या 1177, दिनांक 01 जून, 2016 द्वारा टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण बोर्ड की संरचना का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार गठित टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण के संचालन हेतु वर्तमान में कोई विनियम/नियम अस्तित्व में नहीं है। जिस कारण उक्त प्राधिकरण के संचालन में कठिनाई परिलक्षित हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आवास विभाग द्वारा प्रख्यापित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) को टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण हेतु अधिसूचना संख्या 1783, दिनांक 10 अगस्त, 2016 द्वारा अंगीकार (Adopt) किया गया। उपरोक्तानुसार अंगीकरण (Adoption) पर मा0 मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः उक्त के आलोक में आवास विभाग द्वारा प्रख्यापित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम-2011 (संशोधन 2015) को क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थिति एवं क्षेत्र के पर्यावरण संरक्षण को देखते हुए टिहरी विशेष क्षेत्र पर्यटन विकास प्राधिकरण हेतु अंगीकृत (Adopt) किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए हैं।

आज्ञा से,
शैलेश बगौली,
सचिव।

सिंचाई अनुभाग-1

विज्ञप्ति/प्रोन्नति

30 नवम्बर, 2016 ई0

संख्या 1971/II-2016-01(84)/2003 टी0सी0-1-मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा रिट याचिका संख्या 101/एस0बी0/2016, अमरनाथ सिंह बिष्ट बनाम राज्य तथा अन्य में दिनांक 02-09-2016 को पारित निर्णय के अनुपालन में सिंचाई विभाग के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता स्तर-2 (वेतनमान ₹ 37400-67000 सादृश्य ग्रेड वेतन ₹ 8900/-) के रिक्त पद पर पदोन्नति हेतु दिनांक 05-01-2016 को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक को पुनर्आयोजित (Review) किये जाने हेतु दिनांक 05-10-2016 को आयोजित विभागीय चयन समिति की बैठक द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक् विचारोपरान्त श्री अमरनाथ सिंह बिष्ट, अधीक्षण अभियन्ता (सिविल) की कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के पद पर पदोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. श्री अमरनाथ सिंह बिष्ट को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

आज्ञा से,
आनन्द बर्द्धन,
सचिव।

गृह अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

02 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 1525/XX(1)-2016-3(12)2014-उत्तराखण्ड प्रान्तीय पुलिस सेवा संवर्ग के पुलिस उपाधीक्षक, वेतनमान (₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400) के पद पर प्रोन्नति कोटे की चयन वर्ष 2016-17 की रिक्तियों के विरुद्ध उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार में आयोजित चयन समिति की बैठक दिनांक 28-07-2016 को नियमित चयन हेतु की गयी संस्तुति के आधार पर राज्यपाल महोदय, निम्नलिखित स्थायी पुलिस निरीक्षक को पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत करते हुए कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष के लिए परिवीक्षाकाल पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

क्र०सं०	नाम	अभ्युक्ति
1	2	3
1.	श्री कैलाश चन्द्र पवार	श्री चन्द्र सिंह तितियाल, पुलिस उपाधीक्षक के दिनांक 30-11-2016 की सेवानिवृत्ति से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के सापेक्ष

2. उक्त तालिका में उल्लिखित अधिकारी अपने नाम के सम्मुख स्तम्भ-3 में अंकित अभ्युक्ति में वर्णित अधिकारी के सेवानिवृत्ति के उपरान्त उत्पन्न होने वाली स्पष्ट रिक्ति की तिथि से पदोन्नत किये जा रहे पद पर कार्यभार ग्रहण करते हुए अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे।

3. उपरोक्त पदोन्नति मा० उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-1738 (एस/एस)/2012 में मा० उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी।

आज्ञा से,
विनोद शर्मा,
सचिव।

पर्यटन अनुभाग

अधिसूचना

02 दिसम्बर, 2016 ई०

संख्या 2560/VI(1)/2016-12(05)/2012-अधिसूचना संख्या 114, दिनांक 01 अप्रैल, 2013 द्वारा अधिसूचित उत्तराखण्ड विशेष क्षेत्र (पर्यटन का नियोजित विकास और उन्नयन) अधिनियम, 2013 की धारा 4(1) एवं (2) में दी गयी व्यवस्थानुसार अधिसूचना संख्या 2832, दिनांक 04 सितम्बर, 2013 द्वारा केदारनाथ विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है तथा अधिनियम की धारा 4(2) में दी गयी व्यवस्थानुसार कार्यालय ज्ञाप संख्या 2937, दिनांक 16 सितम्बर, 2013 द्वारा केदारनाथ विकास प्राधिकरण बोर्ड की संरचना का गठन किया गया है।

उपरोक्तानुसार गठित केदारनाथ विकास प्राधिकरण के संचालन हेतु वर्तमान में कोई विनियम/नियम अस्तित्व में नहीं है। जिस कारण उक्त प्राधिकरण के संचालन में कठिनाई परिलक्षित हो रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आवास विभाग द्वारा प्रख्यापित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) को इस उपबन्ध के साथ कि केदारनाथ विकास प्राधिकरण हेतु भवन की ऊँचाई 8.5 मीटर तथा भूतल से अधिकतम 9.0 मीटर अनुमन्य होगी, अंगीकार (Adopt) किये जाने पर मा० मंत्रिमण्डल द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया है।

अतः उक्त आलोक में भवन निर्माण हेतु आवास विभाग द्वारा प्रख्यापित भवन निर्माण एवं विकास उपविधि/विनियम, 2011 (संशोधन 2015) को इस उपबन्ध के साथ कि केदारनाथ हेतु भवन की ऊँचाई 8.5 मीटर तथा भूतल से अधिकतम 9.0 मीटर अनुमन्य होगी, केदारनाथ विकास प्राधिकरण हेतु अंगीकार (Adopt) किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हुए हैं।

भवदीय,
शैलेश बगौली,
सचिव।

गृह अनुभाग-1

विज्ञप्ति/पदोन्नति

09 दिसम्बर, 2016 ई०

संख्या 1575/XX(1)-2016-2(32)2003-भारतीय पुलिस सेवा, उत्तराखण्ड संवर्ग की आई०पी०एस० अधिकारी, श्रीमती विष्मी सचदेवा को सम्यक् विचारोपरान्त पुलिस उपमहानिरीक्षक (वेतनमान ₹ 37400-67000, ग्रेड पे ₹ 8900) के पद पर, तत्काल प्रभाव से एतद्वारा पदोन्नति प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

आज्ञा से,
विनोद शर्मा,
सचिव।

विज्ञप्ति/पदोन्नति

09 दिसम्बर, 2016 ई०

संख्या 1565/XX(1)-2016-2(1)2009-पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या डीजी-एक-117-2000(2), दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 08 दिसम्बर, 2016 पर सम्यक् विचारोपरान्त भारतीय पुलिस सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से भारतीय पुलिस सेवा में कनिष्ठ वेतनमान (₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 5400) से वरिष्ठ वेतनमान (₹ 15600-39100, ग्रेड पे ₹ 6600) में एतद्वारा तत्काल प्रभाव से पदोन्नति प्रदान की जाती है :-

क्र०सं०	अधिकारी का नाम	वैच
1	2	3
1.	सुश्री तृप्ति भट्ट	2013
2.	श्री रामचन्द्र राजगुरु	2013

विनोद शर्मा,
सचिव।



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

रुड़की, शनिवार, दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 ई0 (पौष 03, 1938 शक सम्वत्)

भाग 1-क

नियम, कार्य-विधियां, आज्ञाएं, विज्ञप्तियां इत्यादि जिनको उत्तराखण्ड के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया

HIGH COURT OF UTTARAKHAND, NAINITAL

NOTIFICATION

December 06, 2016

No. 300/UHC/XIV-a/37/Admin.A/2015--Sri Mithilesh Pandey, Judicial Magistrate, Pauri Garhwal is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 18-08-2016 to 05-09-2016.

NOTIFICATION

December 06, 2016

No. 301/UHC/XIV-a/45/Admin.A/2015--Ms. Beenu Gulyani, Judicial Magistrate-I, Haldwani, District Nainital is hereby sanctioned earned leave for 20 days w.e.f. 10-11-2016 to 29-11-2016.

NOTIFICATION

December 06, 2016

No. 302/UHC/XIV-a/26/Admin.A/2016--Sri Sachin Kumar, Judicial Magistrate, Rudrapur, District Udham Singh Nagar is hereby sanctioned earned leave for 12 days w.e.f. 15-11-2016 to 26-11-2016 with permission to prefix 12-11-2016 to 14-11-2016 as second Saturday, Sunday and Kartik Purnima holidays respectively and suffix 27-11-2016 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 07, 2016

No. 303/UHC/XIV-a/47/Admin.A/2012--Ms. Simranjit Kaur, Judicial Magistrate-I, Dehradun is hereby sanctioned child care leave for 101 days w.e.f. 22-08-2016 to 30-11-2016 to 30-11-2016 with permission to prefix 21-08-2016 as Sunday holiday.

NOTIFICATION

December 07, 2016

No. 304/UHC/XIV/38/Admin.A/2008--Ms. Anita Gunjiyal, 2nd Additional Civil Judge (Sr. Div.), Dehradun is hereby sanctioned Maternity leave for 180 days w.e.f. 01-06-2016 to 27-11-2016, in terms of F.R. 101 and S.R. 153 & 154 of F.H.B., Volume-II (Parts 2-4) and Office Memo No. 250/XXVII(7)/2009 dated 24-08-2009 issued by Government of Uttarakhand.

NOTIFICATION

December 08, 2016

No. 305/UHC/XIV-a/44/Admin.A/2015--Ms. Anamika, 1st Additional Civil Judge (Jr. Div.), Nainital is hereby sanctioned earned leave for 34 days w.e.f. 02-11-2016 to 05-12-2016 with permission to prefix 28-10-2016 to 01-11-2016 as public holidays.

NOTIFICATION

December 08, 2016

No. 306/UHC/XIV/35/Admin.A--Ms. Kumkum Rani, District & Sessions Judge, Nainital, is hereby sanctioned earned leave for 19 days w.e.f. 15-11-2016 to 03-12-2016 with permission to prefix 12-14 November, 2016 as second Saturday, Sunday and Kartik Purnima holidays respectively and suffix 04-12-2016 as Sunday holiday for the purpose of L.T.C.

By Order of Hon'ble the Administrative Judge,

Sd/-
Registrar (Inspection).

कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

टनकपुर (चम्पावत)

आदेश

29 सितम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 1749/पंजीयन निरस्त/2016-17-वाहन संख्या UK03TA0547 मॉडल 2012 चैसिस MAT601465CWJ37032 इंजन नं0 14CRAIL08HXYW28369 इस कार्यालय अभिलेखानुसार वाहन स्वामी श्री दीवान सिंह पुत्र श्री पूरन सिंह, पता ग्राम चांचड़ा, पोस्ट दिगालीचौड़, चम्पावत के नाम पर दर्ज है, वाहन स्वामी ने दिनांक 23-08-2016 को आवेदन-पत्र के साथ मूल चैसिस नं0 प्लेट प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि उनका वाहन अग्निकाण्ड में नष्ट हो गया है बीमा कम्पनी द्वारा वाहन को पूर्णक्षति मान कर वाहन का पंजीयन निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29-09-2016 को वाहन संख्या UK03TA0547 चैसिस MAT601465CWJ37032 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

आदेश

30 नवम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 1954/पंजीयन निरस्त/2016-17-वाहन संख्या UP03-0828 मॉडल 1993 चैसिस 344073472054 इंजन नं0 692301451456 इस कार्यालय अभिलेखानुसार (पंजीयन पंजिका अनुसार) वाहन स्वामी श्रीमती मधु अग्रवाल पत्नी श्री राम औतार अग्रवाल, पीलीभीत रोड़, टनकपुर, चम्पावत के नाम पर दर्ज है, दिनांक 05-11-2016 को वाहन स्वामी द्वारा वाहन के पंजीयन निरस्त हेतु (क्योंकि वाहन चलने योग्य नहीं है) आवेदन किया गया है। वाहन फाइनेंस से मुक्त है। प्रवर्तन अनुभाग की आख्या के अनुसार वाहन पर कोई चेक चालान लम्बित नहीं है। सीनियर फोरमैन (उत्तराखण्ड परिवहन निगम) की आख्यानुसार वाहन का मूल चैसिस प्लेट नष्ट कर जमा कर लिया गया है। उक्त तथ्यों के आधार पर वाहन के पंजीयन/चिन्ह के बने रहने का कोई औचित्य नहीं रहता है।

अतः, मैं, रश्मि भट्ट, सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, टनकपुर (चम्पावत) केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 55 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 30-11-2016 को वाहन संख्या UP03-0828 मॉडल 1993 चैसिस 344073472054 को तत्काल प्रभाव से निरस्त करती हूँ।

रश्मि भट्ट,

सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,

(चम्पावत)।

कार्यालय परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रोन्नति/विज्ञप्ति

28 नवम्बर, 2016 ई0

पत्रांक 949/अधि0/दो-161/2016-विभागीय पदोन्नति चयन समिति की बैठक दिनांक 21-11-2016 में की गयी संस्तुति के क्रम में संभागीय संवर्ग के अन्तर्गत कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 9300-34800, ग्रेड वेतन ₹ 4800) के पद पर प्रोन्नत करते हुए उनके नाम के सम्मुख अंकित कार्यालयों में तैनात किया जाता है:-

क्र0 सं0	कार्मिक का नाम सर्वश्री	वर्तमान तैनाती स्थल	पदोन्नति के फलस्वरूप नवीन तैनाती स्थल
1.	नीलकण्ठ जोशी	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, रुड़की	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रुड़की
2.	कु0 प्रमोद मिश्रा	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून
3.	दिनेश कुमार वर्मा	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	कर संग्रह केन्द्र, मंझौला
4.	सुरेखा सपालोक	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून
5.	देवेन्द्र सिंह रावत	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, बागेश्वर
6.	हरि सिंह	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, रुड़की	कर संग्रह केन्द्र, गोवर्धनपुर
7.	सईद अहमद	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हरिद्वार	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, रुड़की
8.	सुषमा चौधरी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऊधमसिंह नगर
9.	संध्या मिश्रा	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश
10.	लक्ष्मी कश्यप	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी
11.	मंगनी हयांकी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	उपसम्भागीय परिवहन कार्यालय, रामनगर
12.	सुरेश चन्द्र बछेती	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	कर संग्रह केन्द्र, कुल्हाल
13.	विनोद भट्ट	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश
14.	दिलबर सिंह गुंसाई	कर संग्रह केन्द्र, कौड़िया	कर संग्रह केन्द्र, नारसन
15.	शांति पाण्डेय	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, हल्द्वानी	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, रामनगर
16.	रुखसाना शम्सी	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून	कर संग्रह केन्द्र, आशारोड़ी
17.	अर्चना शर्मा	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, ऋषिकेश	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून
18.	मनोज नेगी	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, कर्णप्रयाग	कर संग्रह केन्द्र, कौड़िया
19.	भूपेन्द्र सिंह विष्ट	उप सम्भागीय परिवहन कार्यालय, विकासनगर	सम्भागीय परिवहन कार्यालय, देहरादून।

2-उक्त पदोन्नति पूर्णतः अस्थायी है एवं उन्हें किसी भी समय बिना किसी पूर्ण सूचना के उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित किया जा सकता है।

3-सम्बन्धित अधिकारी 02 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि में रहेंगे।

अतः सम्बन्धित नियन्त्रक प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे उक्तानुसार पदोन्नत अधिकारियों को उनके नवीन तैनात स्थलों पर तत्काल कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करें।

सी0एस0 नपलच्याल,
परिवहन आयुक्त।

उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग

अधिसूचना

09 दिसम्बर, 2016 ई0

संख्या 01/प्रशा0/6(4)/उविनिआ/2016-17/1391-विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए एतद्वारा विद्युत सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता है :-

	1.	अध्यक्ष, उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन अध्यक्ष
	2.	सदस्य (वित्त), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	3.	सदस्य (तकनीकी), उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग	पदेन सदस्य
	4.	प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
	5.	प्रमुख सचिव/सचिव, खाद्य एवं रसद, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून	पदेन सदस्य
वाणिज्य एवं उद्योग	6.	अध्यक्ष, इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ऑफ उत्तराखण्ड, देहरादून	सदस्य
	7.	अध्यक्ष, सी0आई0आई0, नेपाल हाऊस, राजपुर रोड, देहरादून	सदस्य
	8.	अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्रीज चैम्बर हाउस, इण्ड0 एरिया, बाजपुर रोड़, काशीपुर	सदस्य
	9.	प्रेसीडेन्ट, उत्तराखण्ड होटल एसोसियेशन, देहरादून	सदस्य
कृषि	10.	निदेशक, कृषि, कृषि निदेशालय, नंदा की चौकी, प्रेमनगर, देहरादून	सदस्य
श्रम	11.	श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड शासन, भोटिया पड़ाव, हल्द्वानी	सदस्य
गैर सरकारी संगठन	12.	डॉ0 अनिल प्रकाश जोशी, हेस्को, ग्राम- शुक्लापुर पोस्ट- अम्बीवाला, प्रेमनगर, देहरादून।	सदस्य
परिवहन	13.	चीफ इलैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन इंजीनियर, उत्तर रेलवे, बडौदा हाऊस, नई दिल्ली	सदस्य
शैक्षणिक एवं अनुसंधान	14.	विभागाध्यक्ष, विद्युत अभियन्त्रण विभाग, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर	सदस्य
	15.	डॉ0 अतुलन गुहा, एसो0 प्रोफेसर, आई0आई0एम0, काशीपुर, उ0सि0नगर	सदस्य
	16.	डॉ0 वी0के0गर्ग, A-24/E, डीडीए फ्लैट्स, मुनरिका, नई दिल्ली	सदस्य
उपभोक्ता प्रतिनिधि	17.	श्री रोहिताश दहिया, F-12, स्वाती अपार्टमेन्ट, आई0पी0 एक्सटेन्शन, नई दिल्ली	सदस्य
	18.	डॉ0 एस0के0कुलश्रेष्ठ, C/o दून कन्ज्यूमर्स एवं प्रोटेक्शन सोसाईटी, 9 ओल्ड सर्वे रोड़, देहरादून	सदस्य
	19.	श्री सुधीर सिंह सिसौदिया, 40, वसन्त विहार फेस-2 देहरादून	सदस्य

विद्युत अधिनियम की धारा 88 के प्राविधानान्तर्गत सलाहकार समिति का दायित्व आयोग को निम्न बिन्दुओं पर सलाह देना है:-

- major questions of policy;
- matters relating to quality, continuity and extent of service provided by the licensees;
- compliance by licensees with the conditions and requirements of their licence;

- (iv) protection of consumers interest; and
- (v) electricity supply and overall standards of performance of utilities.

विद्युत सलाहकार समिति का कार्यकाल इस विज्ञापित के जारी होने की तिथि से एक वर्ष होगा, जब तक कि किसी सदस्य की नियुक्ति विनियम में विहित रीति से इससे पूर्व समाप्त न कर दी जाय।

आयोग की आज्ञा से,
नीरज सती,
सचिव।

UTTARAKHAND ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

December 19, 2016

No. UERC/F(9)-I/RG/UERC/2016/1424: In exercise of the powers conferred by section 181, read with sections 39, 40, 42 and 86 of the Electricity Act, 2003 (36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission hereby proposes the following amendments in the UERC (Terms and Conditions of Intra-State Open Access) Regulations, 2015, (Principal Regulations), namely:-

1. Short Title, Extent and Commencement

- (1) These Regulations may be called the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions of Intra-State Open Access) (First Amendment) Regulations, 2016.
- (2) These Regulations shall come into force from the date of their notification.

2. In Regulation 20 of the Principal Regulation

- (1) The first proviso of Sub-Regulation 2, shall be substituted by:

"Provided where Open Access is allowed up to contracted load, embedded open access consumer shall pay wheeling charges as determined by the Commission in the following manner:

$$WC_{\text{Embedded consumer}} = WC - [FC * 0.85 * 12 * 1000 / 365] \text{ (in Rs./MW/day)}$$

- (2) After the third proviso of the Principal Regulation, the following Proviso shall be inserted, namely:-

"Provided where open access is allowed beyond the contracted load, embedded open access consumer shall pay wheeling charges for the excess load as determined by the Commission in the following manner:

W.C. For excess load allowed = $(ARR-PPC-TC) / (PLSD \times 365) (Rs./MW/Day)$.

3. In Regulation 26 of the Principal Regulation:

(1) After sub-Regulation 2, the following sub- Regulations shall be inserted, namely:-

3. "The open access customer shall abide by the Indian Electricity Grid Code, the State Grid Code as applicable from time to time and instructions given by State Transmission Utility and State Load Dispatch Centre.

4. The open access customer shall also comply with the requirements of the CEA (Technical Standards for Connectivity to the Grid) Regulations, 2007 as amended from time to time.

5. The embedded open access consumer shall schedule for each time block in such a manner that the sum of its total schedule and drawal thereof from all sources including through open access and from Distribution Licensee does not exceed its contracted load with the Distribution Licensee.

Provided further that long term open access may be allowed over and above the contracted load to the extent of sanctioned open access capacity.

Provided also that short term and medium term open access may be allowed over and above the contracted load to the extent of sanctioned open access capacity subject to the condition that it does not require any change in the voltage system, metering system etc., at the interconnection point of the existing consumer and that the resultant power flow on account of such open access can be accommodated in the existing/expected transmission/distribution network in accordance with the provisions of Regulation 11(2) above.

6. The embedded open access consumer shall be levied fixed charges/demand charges based on the maximum demand recorded in the ABT meter as per tariff applicable from time to time.

Provided that if the sanction of open access is allowed over and above the contracted load in terms of proviso to sub-regulation (5) above, the maximum demand for the purpose of charging of fixed charges/ demand charges shall be only in respect of energy supplied by the distribution licensee, i.e. only upto contracted capacity as per the provisions of the Tariff Order.

This maximum demand shall be computed as follows:

$$\frac{\text{Total Maximum Demand Recorded} \times \text{Energy Recorded as supplied by the distribution licensee}}{\text{Total Energy Recorded}}$$

7. The open access customer and embedded open access consumer shall provide the injection/ drawal Schedule, as applicable, every day to the SLDC and the Distribution Licensee before 10:00 AM of the day proceeding the day of such drawal/injection.

8. Annual maintenance outage, other maintenance outage and forced outage shall be subject to the provisions of the State Grid Code as applicable from time to time. Intimation of the forced outage shall be sent to SLDC and to the Distribution Licensees, within 30 minutes of the outage and shall incorporate the estimated outage/rectification time. Restoration of unit under outage shall be conveyed to SLDC at least 30 minutes prior to its synchronization with the State Grid."

4. In Regulation 27 of the Principal Regulation:

- (1) The first proviso of sub-Regulation (2) shall be substituted by:

"Provided that the distribution licensee shall install these Meters within one month from the date on which complete open access application was submitted by the open access customer to the nodal agency with a copy to the distribution licensee."

5. In Regulation 28 of the Principal Regulation:

- (1) In Regulation 28, the heading "Revision" shall be substituted by "Revision of Scheduled Energy and Contract Demand".

- (2) After sub-Regulation (1), the following sub- Regulation shall be inserted, namely:-

"(2) The revision (reduction/enhancement) of contract demand of an embedded open access consumer availing long/medium/short open access shall be governed by the provisions of the UERC (Release of New HT/EHT Connections , Enhancement and Reduction of Loads) Regulations, 2008 and the orders issued under these regulations.

Provided that a consumer availing short term open access shall not be eligible to revise his contract demand with the distribution licensee during the tenure of the short term open access but may apply for revision of contract demand at the time of applying for open access in accordance with the regulations mentioned hereinabove.

Provided further that overall drawal by the embedded open access consumer during the open access period shall not be less than 80% of the overall drawal by such consumer during non open access periods for each day."

6. In Chapter 7 of the Principal Regulation:

- (1) Title of Chapter 7 shall be substituted, namely:-
"DEVIATION SETTLEMENT"

7. In Regulation 30 of the Principal Regulation:

- (1) In Regulation 30, the heading "Imbalance charge" shall be substituted by "Deviation charge".
- (2) In the second sentence of sub-clause (i) of clause (a) the word "imbalance charges" shall be substituted by "deviation charges".
- (3) In the second sentence of sub-clause (ii) of clause (a) the word "imbalance charges" shall be substituted by "deviation charges".
- (4) In the second sentence of sub-clause (i) of clause (b) the words "imbalance charges" shall be substituted by "deviation charges".

- (5) In the second sentence of sub-clause (ii) of clause (b) the words "imbalance charges" shall be substituted by "deviation charges"
- (6) After sub-clause (ii) of clause (b), the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that in case of open access over and above its contracted load in accordance with the proviso to Regulation 26 (5) above, the maximum demand mentioned in clause (i) & (ii) above shall be the maximum demand calculated in accordance with proviso to Regulation 26 (6) above."
- (7) In the second sentence of sub-clause (i) of clause (c) the words "imbalance charges" shall be substituted by "deviation charges".
- (8) In the second sentence of sub-clause (ii) of clause (c) the words "imbalance charges" shall be substituted by "deviation charges".
- (9) In the second sentence of sub-clause (iii) of clause (c) the words "imbalance charges" shall be substituted by "deviation charges".
- (10) The second proviso of sub-clause (iii) of clause (c) shall be substituted, namely:-
"Provided further that the above deviation charges covered in this sub-Regulation (2) is an interim arrangement and shall be applicable till intra-State ABT mechanism is operational in the State where after the Deviation shall be settled based on the Deviation Settlement Account prepared by SLDC in accordance with the Deviation Settlement and related matters Regulations as and when notified by the Commission."

8. In Regulation 31 of the Principal Regulation:

- (1) The proviso shall be substituted, namely:-

"Provided further that after ABT mechanism is operational in the State the reactive energy charges shall be settled based on the State Reactive Energy Account prepared by SLDC in accordance with the State Grid Code and the orders of the Commission issued from time to time."

By Order of the Commission,

NEERAJ SATI,

Secretary,

Uttarakhand Electricity Regulatory Commission.